खंड १७ नंबर २ अप्रैल २०२१

आरआईएस डायरी

–अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

श्री हर्षवर्धन श्रृंगला प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

ऊर्जा पर दक्षिण एशिया समूह का गठन

सेज के सदस्यों की नीतिगत सिफारिशें इस क्षेत्र के नियामकीय ढांचों और दिशा–निर्देशों में अंतर को समाप्त करने में 'गेम–चेंजर' साबित हो सकती हैं।

-श्री हर्षवर्धन श्रृंगला
विदेश सचिव
भारत सरकार

दक्षिण एशिया को विद्युत पारेषण की लागत में कमी करने, खरीदारों एवं विक्रेताओं को एक साथ लाकर बिजली व्यापार की क्षमता का दोहन करने, नियामकीय ढांचे में सामंजस्य स्थापित करने, और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'एकीकृत ग्रिड' की नितांत आवश्यकता है। यह बात भारत के विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने 10 मार्च 2021 को आरआईएस में 'ऊर्जा पर दक्षिण एशिया समूह (सेज)' का गठन करते हुए कही।

श्री श्रृंगला ने अपने संबोधन में भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला, जिनमें बांग्लादेश, भूटान एवं नेपाल जैसे देशों के साथ गैस पाइपलाइन और सीमा–पार अंतर्संबंध शामिल हैं।

क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्री श्रृंगला ने क्षेत्रीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने, और क्षेत्रीय विद्युत अवसंरचना के विकास में निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता की पहचान की। उन्होंने विशेषकर स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों में सहभागिता बढ़ाने और संभावनाओं की पहचान करने का आह्वान किया जो इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम बनाएगा।

उन्होंने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि सेज के सदस्यों की नीतिगत सिफारिशें इस क्षेत्र के नियामकीय ढांचों और दिशा–निर्देशों में अंतर को समाप्त

...शेष पृष्ठ 2 पर

'सेज' के सदस्यों के साथ श्री हर्षवर्धन श्रृंगला।

...पृष्ठ 1 से आगे

करने में 'गेम–चेंजर' साबित हो सकती हैं।

'सेज' के लिए महत्वपूर्ण विचारार्थ विषयों में विद्युत पारेषण कनेक्टिविटी में मौजूद ढांचागत बाधाओं की पहचान करना और इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक उपयुक्त रणनीति सुझाना शामिल हैं। यह पैनल ऊर्जा व्यापार एवं निवेश में संभावनाओं की पहचान भी करेगा और इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में इस सेक्टर से जुड़ी नियामकीय नीतियों में अंतर को समाप्त करने के उपाय सुझाएगा।

इसके अलावा, यह पैनल विद्युत क्षेत्र में बिजली के उत्पादन और पारेषण दोनों में ही प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रीय समाधानों की पहचान करेगा, और क्षेत्रीय परियोजना के वित्तपोषण संबंधी विकल्पों के साथ–साथ इस पहल के लिए धनराशि के स्रोत के बारे में सुझाव देगा। इसके अलावा, यह पैनल परियोजना कार्यान्वयन की योजना बनाने एवं निगरानी के लिए एक संस्थागत ढांचा सुझाएगा और इसके साथ ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों के बारे में प्रस्ताव रखेगा।

वर्तमान में इस क्षेत्र के चार देशों यथा भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच लगभग 3,000 मेगावाट बिजली का व्यापार किया जा रहा है। भारत भूटान से जलविद्युत प्राप्त करता है और इसके साथ ही बांग्लादेश एवं नेपाल को ताप विद्युत और जलविद्युत दोनों की आपूर्ति भी करता है। अन्य देशों के साथ–साथ भूटान पिछले दो दशकों में भारत को जलविद्युत के एक महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत को अधिशेष जलविद्युत (लगभग 1400 मेगावाट) बेचना भूटान के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। बिजली व्यापार के माध्यम से अर्जित राजस्व का इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 25 प्रतिशत योगदान है और इसने इसे सीमेंट एवं स्टील जैसे पूंजी–गहन क्षेत्रों में निवेश करने में सक्षम बनाया है। इसके फलस्वरूप सीमा पार ऊर्जा व्यापार को सभी क्षेत्रीय खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद माना जाता है जो बिजली तक समग्र पहुंच को बेहतर कर सकता है, ऊर्जा उत्पादन संसाधनों का अनुकूलन कर सकता है, और आर्थिक उन्नति एवं विकास की गति को तेज कर सकता है।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में कहा, 'ऊर्जा इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हमें क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में बाह्य आर्थिक जुड़ाव सुनिश्चित करने की नितांत आवश्यकता है।' विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।■

ऊर्जा इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हमें क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में बाह्य आर्थिक जुड़ाव सुनिश्चित करने की नितांत आवश्यकता है।

-प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

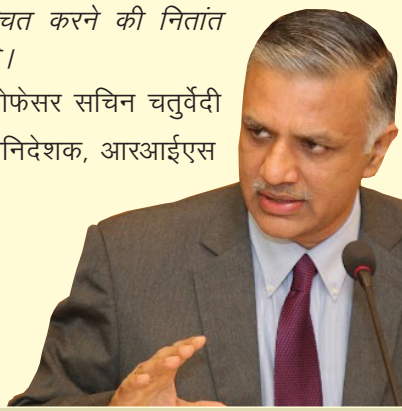

टीकों, दवाओं तक पहुंच और कूटनीति

भारत की वैक्सीन कूटनीतिः सद्भावना उत्पन्न

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद भारत की वैक्सीन कूटनीति पर प्रकाश डालना देश की विकास साझेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। माननीय विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि अब तक 70 से भी अधिक देशों को लगभग 60 मिलियन 'मेड–इन–इंडिया कोविड–19 वैक्सीन खुराकों' की आपूर्ति की जा चुकी है जिससे दुनिया भर में सद्भावना उत्पन्न हो रही है और भारत की वैश्विक साख बढ़ रही है।

आरआईएस द्वारा 20–21 मार्च 2021 को आयोजित भारतीय विकास सहयोग फोरम (एफआईडीसी) की पहली वार्षिक संगोष्ठी, जिसे 'विकास सहयोग संवाद' के रूप में पेश किया जा रहा है, को संबोधित करते हुए श्री मुरलीधरन ने 'विकास साझेदारी' को भारत की विदेश नीति के एक प्रमुख अवयव के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि भारत की विकास साझेदारी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह मानव केंद्रित है और सतत विकास पर आधारित है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत की विकास साझेदारी में कोई भी आदेशात्मक या दोहन करने की शर्त नहीं है, और इसके बजाय यह भागीदार देशों को अपनी क्षमता को हासिल करने का अवसर प्रदान करती है।

मंत्री महोदय ने कहा, 'कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद भारत ने आवश्यक दवाएं भेजकर दुनिया भर के देशों को मानवीय सहायता प्रदान की है, भारत विभिन्न वेबिनार मॉड्यूल के माध्यम से क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, त्वरित कार्रवाई दलों को भेज रहा है, और सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म (दक्षिण एशिया में) विकसित कर रहा है।' उन्होंने कहा कि इन प्रयासों ने वैश्विक संकट के इस समय में अन्य विकासशील देशों के साथ भारत की एकजुटता को भी दर्शाया है।

उन्होंने ये बातें ऐसे समय में कही हैं जब महामारी के मौजूदा प्रकोप के साथ–साथ संसाधनों के सृजन में वैश्विक

क्षमता पर महामारी के प्रभाव के कारण एजेंडा 2030 को अपनी पूर्व–निर्धारित समय–सीमा के भीतर बनाए रखने से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर विकास सहयोग का महत्व काफी बढ़ गया है।

अनुदान सहायता, ऋण रेखा (एलओसी) के साथ–साथ क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता सहित भारत की विकास साझेदारी के विभिन्न तत्वों का उल्लेख करते हुए श्री मुरलीधरन ने कहा कि अनुदान सहायता के रूप में 4 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक दिए गए हैं जो बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा एवं सद्भावना उत्पन्न करने वाले स्वास्थ्य और दीर्घकालिक साझेदारी सहित अनेक क्षेत्रों को कवर करती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत ने 64 देशों को कुल 31.6 अरब अमेरिकी डालर की 311 एलओसी प्रदान की है जो विकासशील देशों में सामाजिक–आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण से जुड़ी 657 परियोजनाओं को कवर करती हैं। उन्होंने कहा कि इन एलओसी की बदौलत भारत से विदेशी बाजारों को बिजली, परिवहन, कनेक्टिविटी, कृषि, सिंचाई और विनिर्माण सहित अनेक क्षेत्रों से जुड़ी वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि भारत की विकास साझेदारी के तहत 'एक्ट ईस्ट' नीति सहित अपने पड़ोस में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित पहलों पर भी केंद्रित किया जाता रहा है। अब तक 7.69 अरब अमेरिकी डॉलर की इस तरह की 104 परियोजनाओं का कार्यान्वयन हाथ में लिया गया है, जिनमें से 47 पूरी हो गई हैं, और ये दो देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्कों के साथ–साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने क्षमता निर्माण पर भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रमों के साथ–साथ दक्षिण पूर्व एशिया में मंदिरों सहित धरोहर स्थलों के संरक्षण और बहाली के जरिए विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी विस्तार से बताया।

भारत के विकास सहयोग पर एक बहु–हितधारक प्लेटफॉर्म के रूप में एफआईडीसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के विकास सहयोग संबंधी अनुभवों पर विचार–विमर्श एवं साझा करने और इनका प्रचार–प्रसार करने के लिए सिविल सोसायटी, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं

...शेष पृष्ठ 6 पर

आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

टीकों, दवाओं तक पहुंच और कूटनीति

नवाचार एवं टीकों तक पहुंच और स्वास्थ्य प्रभाव कोष

आरआईएस ने 19 जनवरी 2021 को नवाचार एवं टीकों तक पहुंच और स्वास्थ्य प्रभाव कोष (एचआईएफ) पर एक वेबिनार का आयोजन किया। एचआईएफ दरअसल दवाओं एवं फार्मास्यूटिकल्स में नवाचार को प्रोत्साहित करने और बेहतर पहुंच को सक्षम करने के लिए एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थॉमस पोगे द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है। इस वेबिनार का आयोजन सार्वजनिक स्वास्थ्य पर शिक्षाविदों, उद्योग के प्रतिनिधियों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए किया गया था, ताकि टीकों तक पहुंच, उनमें नवाचार के मुद्दों पर चर्चाएं की जा सकें।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में टीकों तक पहुंच के मुद्दे के साथ–साथ इस बात पर भी प्रकाश डाला कि क्यों नवाचार से अक्सर पर्याप्त पहुंच संभव नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने पहुंच और नवाचार दोनों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं की पहचान करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। डॉ. एस. आर. राव, उपाध्यक्ष, श्री बालाजी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पांडिचेरी और पूर्व सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने इस सत्र की अध्यक्षता की और नवाचार के लिए विभिन्न विकल्पों पर बहस की आवश्यकता को रेखांकित किया। अपनी प्रस्तुति में प्रोफेसर पोगे ने एचआईएफ की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और यह दलील दी कि यह विकासशील देशों को टीकों एवं

अन्य आवश्यक दवाओं के साथ–साथ उपेक्षित बीमारियों की दवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में आखिरकार कैसे मदद कर सकता है। उन्होंने बताया कि एचआईएफ दरअसल पहुंच को सक्षम करने के लिए अन्वेषकों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि प्रभाव के अधिक होने पर वे अधिक लाभान्वित होते हैं। प्रोफेसर एडन हॉलिस ने अपनी प्रस्तुति में एचआईएफ की काफी वकालत करते हुए इस ओर ध्यान दिलाया कि पायलट कार्यक्रमों के माध्यम से इसे आजमाना उचित रहेगा और इसके साथ ही उन्होंने विकसित एवं विकासशील देशों में लोगों तक पहुंच में भारी असमानताओं को देखते हुए किफायती टीके और दवाएं लाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।

श्री अशोक मदान ने उद्योग के नजरिए से अवगत कराया और जेनरिक के महत्व के बारे में विस्तार से बताया और इसके साथ ही यह भी बताया कि जेनेरिक उद्योग ने किस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य में अहम योगदान दिया है। एचआईएफ के बारे में उन्होंने यह संकेत दिया कि उद्योग इसके खिलाफ नहीं होगा। डॉ. मुरली ने बायोफार्मा उद्योग के नजरिए से अवगत कराया और बेहतर एवं अधिक नवाचार के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि एचआईएफ के लिए अधिक अन्वेषण जरूरी है और इसके साथ ही व्यापक सहयोग देने की आवश्यकता है। डॉ. वाई. माधवी ने वर्ष 1947 के बाद भारत में टीके के विकास एवं उपलब्धियों और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा की। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि टीकों में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए था और इसके लिए आवश्यक सहयोग दिया जाना चाहिए था। प्रोफेसर पोगे ने भारत में एचआईएफ पर दर्शकों और पैनलिस्टों की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब दिए। डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास ने धन्यवाद ज्ञापन किया। ■

सार्वजनिक नीति और आर्थिक विकासः भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग पर अध्ययन

आरआईएस ने 'सार्वजनिक नीति और आर्थिक विकासः भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग की केस स्टडी' पर वाणिज्य मंत्रालय की ओर से किए जा रहे फार्मास्युटिकल अध्ययन पर 20 जनवरी 2021 को वर्चुअल परिचर्चा का आयोजन किया। विविध पृष्ठभूमि के विशेषज्ञों को इस अध्ययन के निष्कर्षों को साझा करने और इस पर अपने विचार एवं सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था, ताकि यह अध्ययन नीति निर्माताओं के लिए और भी अधिक उपयोगी साबित हो सके।

प्रमुख विशेषज्ञ ये थेः श्री श्यामल मिश्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय; डॉ. एस.जे. एस. फ्लोरा, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (नाइपर); डॉ. ज्ञानेंद्र नाथ सिंह, पूर्व औषधि महानियंत्रक; श्री वी.वी. कृष्णा रेड्डी, अध्यक्ष, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (बीडीएमए); श्री अशोक कुमार मदान, कार्यकारी निदेशक, इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए); श्री सुदर्शन जैन, महासचिव, इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस (आईपीए); श्री प्रवीण के. मित्तल, वरिष्ठ निदेशक, फिक्की; श्री लंका श्रीनिवास, एलिक्स ग्लोबल; श्री रघु कोचर, उपाध्यक्ष, काउंसिल फॉर हेल्थकेयर एंड फार्मा (सीएचपी); और श्री अरुण साहनी, पूर्व सीईओ, रैनबैक्सी, इत्यादि।

...शेष पृष्ठ 5 पर

...पृष्ठ 4 से आगे

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में इतनी विशाल आबादी वाले भारत जैसे देश के लिए दवा उद्योग के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। आरआईएस के विशिष्ट फेलो श्री राजीव खेर, जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की, ने अपने उद्घाटन भाषण में विशेषकर वर्ष 2005 के बाद इस उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों जैसे कि अनुसंधान एवं विकास में निवेश, जैव प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक प्रणाली, इत्यादि की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री श्यामल मिश्रा ने दुनिया भर में भारतीय जेनेरिक दवाओं और टीकों के बढ़ते महत्व, मान्यता, एवं विश्वसनीयता को रेखांकित किया और इसके साथ ही आने वाले वर्षों में विशेषकर गुणवत्ता मानकों, नियामकीय सुविधा, इत्यादि के क्षेत्र में निरंतर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संबंधित चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया। डॉ. दिनेश कुमार, आरआईएस और डॉ. दीपिका चावला, आरआईएस द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। इसके बाद इस अध्ययन पर विशेषज्ञों द्वारा व्यापक अवलोकन किए गए जिनके तहत विशेषकर अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए 352 एबी– निगेटिव प्रोत्साहन को हाल ही में

वापस लिए जाने और किण्वन–आधारित बल्क ड्रग्स उद्योग, जिसमें अन्य बातों के अलावा पूंजी–गहन और समय–अंतराल भी अत्यंत व्यापक है, द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय बाधाओं पर प्रकाश डाला गया। इस अध्ययन के दायरे को और भी अधिक व्यापक बनाने का भी सुझाव दिया गया, जिसके तहत विशेषकर उन पेटेंट प्राप्त दवाओं की पहचान करने पर जोर दिया गया जिनका पेटेंट जल्द ही समाप्त होने वाला है। निर्यात को और बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों, विशेषकर यूरोपीय देशों के साथ समझौता या पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) करने; दुनिया भर में भारतीय औषधकोश (फार्माकोपिया) की अधिक मान्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने; बायोसिमिलर एवं बायोलॉजिक्स के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक नियामकीय प्रोत्साहन/सुविधा देने; घरेलू दवा उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकों को उन्नत करके आखिरकार कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप किया जा सकता है, इस बारे में भी अध्ययन करने के सुझाव दिए गए। आरआईएस के प्रोफेसर टी.सी. जेम्स ने समापन भाषण दिया और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण अवलोकन एवं सुझाव प्रदान करने के लिए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। ■

वित्त, बैंकिंग और प्रौद्योगिकी

भारत में घटती बचत दर – नए नीतिगत विकल्प

आरआईएस और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने बैंकों एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े समूचे परिदृश्य का विश्लेषण करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए आपसी साझेदारी में वेबिनार की श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला में पहली पैनल परिचर्चा 20 जनवरी 2021 को 'भारत में घटती बचत दर – नए नीतिगत विकल्प' पर आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण से हुई। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) के अध्यक्ष श्री एन. एन. वोहरा ने उद्घाटन भाषण दिया। श्री रजनीश कुमार, पूर्व चेयरमैन, भारतीय स्टेट बैंक ने पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता की। पैनलिस्टों में ये शामिल थे: प्रोफेसर अनंत नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर (सहायक), सार्वजनिक नीति के प्रमुख, एसपीजेआईएमआर, मुंबई; डॉ. अमेय सप्रे, सहायक प्रोफेसर, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली; और प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल, सीनियर एडजंक्ट फेलो, आरआईएस।

वेबिनार में इस बात पर आम सहमति थी कि हमें दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए नए प्रपत्रों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की जरूरत है। पेंशन फंडों को भी सक्रिय करने की आवश्यकता है। डेटा संबंधी सीमाओं पर काम किया जाना चाहिए। जमाराशियों को बेहतर रिटर्न के साथ सुरक्षित होना चाहिए। अधिकारियों को इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि किस तरह के प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएं और किस तरह के उत्पाद निश्चित रूप से बचत को आकर्षित करेंगे और बेहतर एवं तेज विकास हेतु लाभकारी निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी के कुल कोष या धनराशि में वृद्धि करेंगे। ■

डिजिटल भुगतान और क्यूआर कोडः आगे की राह

32वां विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (स्टिप) फोरम व्याख्यान 23 जनवरी 2021 को प्रोफेसर दीपक बी. फाटक, प्रोफेसर एमेरिटस, आईआईटी–बॉम्बे ने 'डिजिटल भुगतान और क्यूआर कोडः आगे की राह क्या है?" विषय पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया। डॉ. किरण कार्णिक, चेयरमैन, रीबिट और पूर्व अध्यक्ष, नैसकॉम ने सत्र की अध्यक्षता की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद टेरी के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर और आईएचसी के निदेशक श्री सुनीत टंडन ने भाषण दिए। अपने उद्घाटन भाषण में प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने प्रौद्योगिकी के साथ वित्तीय क्षेत्र के जुड़ाव की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और यह बताया कि कैसे इसने भारत में वित्तीय लेन–देन और भुगतान प्रणालियों में व्यापक बदलाव लाया है।

प्रोफेसर दीपक बी. फाटक ने समय के साथ भुगतान प्रणालियों के विकास की व्याख्या करते हुए अपने अत्यंत सहज व्याख्यान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने वस्तु विनिमय प्रणाली से मुद्रा में और फिर मुद्रा से वित्तीय प्रपत्रों जैसे कि चेक में बदलने की बात कही। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग प्रणालियों में स्वचालन के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे डिजिटल भुगतान की प्रणाली संभव हो पाई और जिसमें स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट–बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग शामिल हैं। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है और सावधानियां बरत रहा है कि डिजिटल भुगतान से लोगों को हो रही सहूलियत और सुरक्षा एवं हिफाजत (जैसे कि साइबर चोरी, इत्यादि) के बीच संतुलन अवश्य बना रहे।

इसके बाद प्रोफेसर फाटक ने भारत में डिजिटल भुगतान की ताजा स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जिसके तहत उन्होंने आरटीजीएस, एनईएफटी, एसएफएमएस, यूपीआई (भीम), आईएमपीएस, रुपे डेबिट कार्ड, 'आधार' पर आधारित केवाईसी मानक जैसी कुछ सफल भारतीय पहलों के बारे में बताया। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि भारत में 'दो तरीकों से सत्यापन (सीवीवी एवं ओटीपी)' कई विकसित देशों में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित प्रक्रिया है।

वक्ता ने आगे यह बताया कि क्यूआर (क्विक रिस्पांस) कोड का विकास किस तरह से हुआ। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड का आविष्कार जापान में वर्ष 1995 में हुआ था और यह अपने पूर्ववर्ती कोड यानी 'बार कोड' की तुलना में हाल ही में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने कहा कि कैमरा युक्त मोबाइल फोन की व्यापक उपलब्धता और उपयोग से ही इस नए कोड को व्यापक रूप से अपनाना संभव हो पा रहा है। बार कोड, जिसे स्कैन करने के लिए विक्रेता अथवा दुकानदार की डेस्क या टेबल पर एक पीओएस डिवाइस को लगाने की आवश्यकता होती है, के विपरीत क्यूआर कोड को ग्राहकों के मोबाइल फोन के कैमरे का उपयोग करके आसानी से और जल्दी से स्कैन किया जा सकता है। इसकी बदौलत यहां तक कि पारंपरिक पीओएस डिवाइस के बिना भी डिजिटल भुगतान करना संभव है।

प्रोफेसर फाटक ने आगे की राह का उल्लेख करते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया कि देश में होने वाले सभी खुदरा लेन–देन में डिजिटल लेन–देन की हिस्सेदारी को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, जिसका मतलब यही है कि नकद लेन–देन को आदर्श रूप से शून्य हो जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने 'आधार' सत्यापन को और भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि अल्पावधि में कारोबारियों को इससे जोड़ने का काम निरंतर जारी रहना चाहिए और ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) एवं कमोडिटी (वस्तु या जिंस) विक्रेताओं द्वारा क्यूआर कोड का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। आखिर में, अध्यक्ष डॉ. किरण कार्णिक ने अपने संबोधन में ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों के मद्देनजर डिजिटल मुद्राओं के भविष्य के बारे में संकेत दिया और इसके साथ ही साइबर संबंधी संभावित किफायत के मद्देनजर डिजिटल लेन–देन की मजबूती के बारे में बताया। ■

भारत की वैक्सीन कूटनीतिः सद्भावना उत्पन्न

...पृष्ठ 3 से आगे

को एक साथ लाता है। कोरोना वायरस की वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए विकास सहयोग का महत्व काफी बढ़ गया है, और इसके साथ ही अन्य देशों को भारत का समर्थन और भी अधिक मजबूत हो गया है।

मौजूदा हालात को देखते हुए 'एफआईडीसी वार्षिक संगोष्ठी 2021: विकास सहयोग संवाद' हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया, ताकि इस आशय का एक स्पष्ट और प्रभावकारी रोडमैप तैयार किया जा सके। राजदूत डॉ. मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस; प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; और डॉ. राजेश टंडन, अध्यक्ष एफआईडीसी एवं अध्यक्ष, प्रिया ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का विवरण आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ■

भारत के साथ त्रिकोणीय सहयोग में वैश्विक रुझान

आरआईएस और ओईसीडी के विकास सहयोग निदेशालय (डीसीडी) ने प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी एवं डॉ. नादिन पिफर–सोयलर के एक शोध–पत्र (पेपर) 'भारत के साथ त्रिकोणीय सहयोग में वैश्विक रुझान . सिविल सोसायटी संगठनों के साथ बेहतर सहयोग के लिए उभरते नीतिगत विकल्प' के विमोचन के लिए 25 जनवरी 2021 को एक वेबिनार का आयोजन किया। इस शोध–पत्र के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए इस वर्चुअल कार्यक्रम में सरकारों, सिविल सोयायटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधिगण एकजुट हुए।

इस कार्यक्रम की शुरुआत ओईसीडी विकास सहयोग निदेशालय (डीसीडी) के निदेशक श्री जॉर्ज मोरेरा डा सिल्वा के स्वागत और मंचन के साथ हुई। श्री अखिलेश मिश्रा, अपर सचिव, विकास भागीदारी प्रशासन, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने त्रिकोणीय सहयोग में भारत की रुचि पर आरंभिक भाषण दिया। ओईसीडी विकास सहायता समिति (डीएसी) की अध्यक्ष डॉ. सुसाना मूरहेड ने भारत के साथ काम करने में डीएसी की रुचि के बारे में बताया, जिसमें त्रिकोणीय साझेदारियों के जरिए काम करना भी शामिल है। डॉ. राजेश टंडन, अध्यक्ष, भारतीय विकास सहयोग फोरम (एफआईडीसी) और संस्थापक– अध्यक्ष, प्रिया ने त्रिकोणीय सहयोग पर एफआईडीसी और सीएसओ से जुड़े परिप्रेक्ष्य के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. एना फर्नांडिस, प्रमुख, दूरदर्शिता, आउटरीच और नीतिगत सुधार (फॉर) यूनिट, ओईसीडी/डीसीडी ने इन लेखकों के साथ परिचर्चा का संचालन किया: प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और डॉ. नादिन पिफर–सोयलर, ओईसीडी डीसीडी / दूरदर्शिता, आउटरीच और नीतिगत सुधार (फॉर) यूनिट। इसके बाद प्रख्यात प्रतिभागियों के साथ चर्चा हुई जिनमें विकास विकल्प बोर्ड के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. अशोक खोसला; डॉ. करेन क्लिमोवस्की, उप मिशन निदेशक, यूसेड इंडिया; सुश्री रेनाना झाबवाला, स्व–रोजगार महिला संघ (सेवा) भारत बोर्ड की अध्यक्ष; और डॉ. कार्लोस कॉररिया, कार्यकारी निदेशक, दक्षिण केंद्र शामिल थे।

इस शोध–पत्र में 1950 के दशक की शुरुआत से ही त्रिकोणीय सहयोग में भारत की सहभागिता पर प्रकाश डाला गया है। त्रिकोणीय सहयोग से जुड़ी परियोजनाओं को मुख्यतः सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ), निजी क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों और अन्य गैर–सरकारी चैनलों के माध्यम से लागू किया गया है। 1950 के दशक में भारत त्रिकोणीय सहयोग के विभिन्न तौर–तरीकों से जुड़ गया था जिनमें विशेषज्ञता साझा करने के लिए त्रिकोणीय साझेदारियां, प्रवासियों के लिए संयुक्त त्रिकोणीय सहयोग, भारत की ओर से संसाधन के योगदान के साथ त्रिकोणीय साझेदारियां, त्रिकोणीय साझेदारियों में भारतीय सिविल सोसायटी संगठनों की सहभागिता के लिए सहयोग शामिल थे।

रामकृष्ण मिशन के माध्यम से ही भारत पहली बार त्रिकोणीय सहयोग में शामिल हुआ था। वर्ष 1964 में भारत ने विकासशील देशों के साथ अपने तकनीकी सहयोग को

...शेष पृष्ठ 16 पर

एसडीजी 2 के लिए एसटीआई रोडमैप

आरआईएस ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 27 जनवरी 2021 को 'एसडीजी 2 के लिए एसटीआई रोडमैप तैयार करना: भारत के लिए प्रौद्योगिकी के अधिशेष और कमी का संकेतक आधारित आकलन' विषय पर प्रथम राष्ट्रीय स्तर की वर्चुअल गोलमेज चर्चा की मेजबानी की। यह कार्यशाला एसडीजी के लिए एसटीआई रोडमैप तैयार करने में भारत की राष्ट्रीय पहल का हिस्सा थी। इस गोलमेज चर्चा में दो सत्र शामिल थे। पहला सत्र पोषण सुरक्षा पर था जिसमें पोषण और सक्षम या संभव खाद्य प्रसंस्करण एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों के मुद्दों को कवर किया गया। दूसरे सत्र में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं निरंतरता के मुद्दों और सतत खाद्य प्रणालियों एवं आईसीटी प्रौद्योगिकियों में उभरने वाले संबंधित नवाचारों को कवर किया गया।

डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद पीएसए के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव डॉ. अरबिंद मित्रा ने विशेष भाषण दिया। उद्घाटन भाषण भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन ने दिया। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि कृषि में एसटीआई संबंधी ठोस उपाय अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बीसवीं शताब्दी में औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन और वितरण प्रणालियों की परिकल्पना की गई थी जो आज के समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसके अलावा, उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख किया जिनमें एसटीआई भारत में कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की पेशकश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उपर्युक्त क्षेत्र ये थे: ए) बिजली एवं पानी तक पहुंच बढ़ाना बी) जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ठोस उपाय करना सी) ऐसे विकेंद्रीकृत स्थानीय समाधानों का पता लगाना जो भौगोलिक संदर्भ के लिए विशिष्ट हों और डी) डेटा की उपलब्धता एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं से कनेक्टिविटी।

'पोषण सुरक्षा की ओर' विषय पर आयोजित पहले सत्र का संचालन पीएसए के कार्यालय में ओएसडी डॉ. आयशा चौधरी ने किया। सत्र की शुरुआत डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस द्वारा दी गई एक प्रस्तुति के साथ हुई जिन्होंने आरआईएस में एसडीजी के लिए एसटीआई रोडमैप विकसित करने के लिए निरंतर जारी कार्य पर प्रकाश डाला। इसके बाद सत्र के विभिन्न वक्ताओं ने प्रस्तुतियां दीं, जो ये थे: सुश्री अदिति दास राउत, संयुक्त सचिव (पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; डॉ. सी. वासुदेवप्पा, कुलपति, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम); डॉ. प्रवीण मलिक, पशुपालन आयुक्त, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय; और डॉ. बी. दयाकर राव, प्रधान वैज्ञानिक एवं सीईओ, न्यूट्रीहब, टीबीआई, आईसीएआर–भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान।

इस सत्र में चिन्हित किए गए प्रमुख मुद्दे ये थे: 1) भारतीय आहार प्रणाली, विशेषकर पीडीएस के माध्यम से वितरित भोजन में पोषण की कुल मात्रा (सूक्ष्म पोषक तत्व एवं विटामिन) और उच्च कैलोरी सेवन की कमी, 2) खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने/बढ़ाने के लिए सहायक बुनियादी ढांचागत सुविधाओं (उदाहरण के लिए कोल्ड स्टोरेज, जैव–सृदृढ़ीकरण जैसी नई खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, इत्यादि) की कमी 3) आपूर्ति श्रृंखलाओं के असंगठित नेटवर्क 4) घटिया मानकों वाली प्रणाली जो निर्यात को सीमित कर देती है, और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में वित्तपोषण की कमी। इस सत्र में सार्वजनिक सेवा वितरण में अमल में लाए गए कई सफल एसटीआई उपायों जैसे कि पोषण एटलस, राष्ट्रीय मानसून मिशन, इत्यादि और बाजरे के प्रसंस्करण से संबंधित अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने पर भी प्रकाश डाला गया।

सतत और सुदृढ़ कृषि' पर आयोजित दूसरे सत्र का संचालन डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास, सलाहकार, आरआईएस ने किया। इस सत्र में भाग लेने वाले वक्ताओं में ये शामिल थे: सुश्री जोआना केन–पोटाका, एडीजी (बाह्य संबंध), इक्रीसैट; डॉ. श्रीकांत रूपावतरम, वैज्ञानिक, डिजिटल कृषि, इक्रीसैट (एआई और कृषि); श्री रोशन लाल तमक, कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ (चीनी का कारोबार), डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, और डॉ. प्रवीर देशमुख, सलाहकार, सतत विकास के लिए सीआईआई–आईटीसी उत्कृष्टता केंद्र।

इस सत्र में चर्चा वाले प्रमुख मुद्दे ये थे: 1) उभरती प्रौद्योगिकियों का किफायती होना 2) संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करना 3) गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल/मशीनीकरण तक पहुंच 4) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण 5) घटता या गिरता मृदा स्वास्थ्य और जल संरक्षण 6) 'मुख्य उपज' से विविधीकरण करना। इस सत्र के दौरान इस क्षेत्र में, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जारी कुछ पहलों पर भी प्रकाश डाला गया। इन दोनों ही सत्रों का समापन वक्ताओं के बीच संक्षिप्त चर्चा के साथ हुआ। ■

एसडीजी 6: भारत के लिए प्रौद्योगिकी के अधिशेष का आकलन

आरआईएस ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 25 मार्च 2021 को 'एसडीजी 6 के लिए एसटीआई रोडमैप तैयार करना: भारत के लिए प्रौद्योगिकी के अधिशेष और कमी का संकेतक आधारित आकलन' पर परामर्श बैठक की मेजबानी की। इस दौरान चर्चा एसडीजी–6 के अंतर्गत तीन प्रमुख क्षेत्रों यथा पेयजल, जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन, और जल प्रदूषण पर केंद्रित रही। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद पीएसए के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव डॉ. अरबिंद मित्रा ने विशेष भाषण दिया।

उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि एक प्रभावकारी एसटीआई रोडमैप बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग अत्यंत आवश्यक है जिनमें उद्योग, शिक्षाविद, स्टार्ट–अप्स और सरकार शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह की साझेदारियों के प्रयासों में ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं जो वैश्विक भलाई में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

डॉ. मित्रा के भाषण के बाद हुई परिचर्चा का संचालन डॉ. पी. के. आनंद, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने किया। इसकी शुरुआत डॉ. सब्यसाची साहा, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुति देने के साथ हुई, जिन्होंने आरआईएस में एसडीजी के रोडमैप हेतु एसटीआई विकसित करने के लिए निरंतर जारी कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रत्येक वक्ता ने प्रस्तुति दी/भाषण दिया। वक्ताओं में ये सभी शामिल थे: डॉ. संजय बाजपेयी, प्रमुख, प्रौद्योगिकी मिशन प्रभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय; डॉ. एम. दीनदयालन, सलाहकार (पीएचईई), केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन, आवास व शहरी कार्य मंत्रालय; डॉ. पवन लाभसेत्वंर, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, जल प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रभाग, सीएसआईआर–नीरी; डॉ. डी. ज्ञानसुंदर, निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना; श्री सुनील कुमार, निदेशक (बेसिन योजना– 1), केंद्रीय जल आयोग, श्री वी.के. माधवन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाटर एड इंडिया; और श्री के श्री हर्ष, संस्थापक, कृत्सनाम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।

बैठक में निर्धारित किए गए प्रमुख मुद्दे ये थे: प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए सामाजिक स्वीकार्यता एवं पर्यावरणीय चिंतन–मनन; जल गुणवत्ता के गतिशील स्वरूप को देखते हुए जल संवर्धन/शुद्धि करण प्रौद्योगिकियों का विकास; उच्च गैर–राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) (30–60:); जल वितरण नेटवर्क में नई तकनीकों जैसे कि सेंसर, एआई, इत्यादि का उपयोग; एक सामान्य मानक के सापेक्ष प्रौद्योगिकियों के मानदंड तय करना; एक मजबूत एवं सामान्य या आम जल स्रोत सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए जल स्रोतों का मानचित्रण; सतही जल के भंडारण पर फोकस करते हुए जल अवसंरचना का विकास; वर्षा जल के संचयन के लिए सहायक अवसंरचना की कमी; और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में धूसर जल के प्रबंधन की योजना बनाना। ■

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारत–ताइवान सहयोग

आरआईएस और प्रॉस्पेक्ट फाउंडेशन, ताइपे द्वारा 25 फरवरी 2021 को संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में बहु–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और ताइवान के प्रमुख हितधारक एकजुट हुए। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और डॉ. आई–चुंग लाई, प्रेसिडेंट, प्रॉस्पेक्ट फाउंडेशन द्वारा दिए गए आरंभिक भाषणों में इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों पर फोकस करने के साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत और ताइवान के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने आरआईएस और प्रॉस्पेक्ट फाउंडेशन के बीच साझेदारी को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि इन सहयोगों को मूर्त रूप देने के लिए नीतिगत रोडमैप तैयार किए जा सकें और फिर इन्हें नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, जिसके लिए वेबिनार आगे की राह हो सकता है। इस कार्यक्रम में ये चार व्यापक विषय कवर किए गए – विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं वैश्विक आर्थिक व्यवस्था; आईसीटी और सेमीकंडक्टर उद्योग; स्मार्ट विनिर्माण एवं उद्योग 4.0, और भारत एवं ताइवान में विज्ञान पार्क– पारस्परिक रूप से सीखने के लिए अनुभव और गुंजाइश।

पहले सत्र में वैश्विक आर्थिक परिवेश से जुड़े प्रमुख रुझान पर फोकस किया गया और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सही स्वरूप देने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का आकलन किया गया। दूसरे सत्र में आईसीटी और सेमीकंडक्टर से जुड़े भारत के नीतिगत दृष्टिकोण के साथ–साथ ताइवान के नीतिगत दृष्टिकोण का भी अवलोकन प्रस्तुत किया गया। तीसरे सत्र में भारत एवं ताइवान में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग व मशीन टूल्स के विकास और आपस में सीखने और सहयोग की गुंजाइश पर फोकस किया गया। चौथे एवं अंतिम सत्र में भारत में विज्ञान पार्कों और विभिन्न क्लस्टरों के विकास पर चर्चा हुई।

भारत की ओर से प्रमुख वक्ता ये थे: डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस; प्रोफेसर वी. कामाकोटि, आईआईटी–मद्रास; श्री

...शेष पृष्ठ 13 पर

संयुक्त राष्ट्र@75 और दक्षिणीय सहयोगः उभरती भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

आरआईएस और जर्मन विकास संस्थान (जीडीआई)/ड्यूशेज इंस्टीट्यूट फर एंटविकलुंगस्पोलिटिक (डीआईई) ने 16 फरवरी 2021 को 'संयुक्त राष्ट्र@75 और दक्षिणीय सहयोगः उभरती भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों' पर एक वेबिनार की सह–मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव श्री बान की मून ने मंगलवार को इस वेबिनार में अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि पारंपरिक दानदाता यानी अमीर राष्ट्र ऐसे समय में सहायता राशि में कटौती कर रहे हैं जब विकासशील

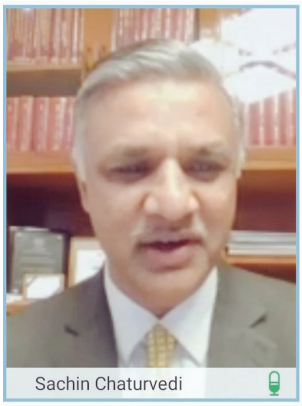

देशों को अपनी बजटीय सीमाओं के कारण बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

इस ओर ध्यान दिलाते हुए कि राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद बहुपक्षीय सहयोग में बाधा बन रहे हैं, उन्होंने वैश्विक समुदाय से यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाने को कहा कि लचीले, जवाबदेह और देश संचालित उपायों के माध्यम से महत्वपूर्ण संसाधन जरूरतमंदों तक अवश्य ही पहुंच जाएं। श्री मून की टिप्पणियों का विशेष महत्व है क्योंकि वैश्विक विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने वैक्सीन राष्ट्रवाद और उन निर्यात पाबंदियों के खिलाफ आगाह किया है जिनकी वजह से विशेषकर गरीब देशों में कोविड–19 वैक्सीन का वितरण बाधित हो रहा है और इसके चलते आर्थिक बेहतरी की गति धीमी हो रही है।

श्री मून, जो 'द एल्डर्स (वैश्विक नेताओं का एक स्वतंत्र समूह)' के उपाध्यक्ष हैं, ने

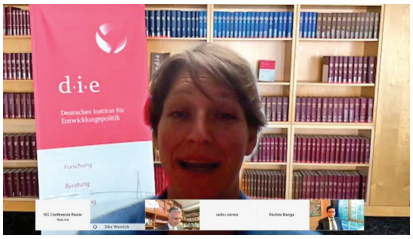

इस ओर भी ध्यान दिलाया कि विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के कई देशों को वर्ष 2021 में बढ़ती बजटीय सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'पारंपरिक दानदाता ऐसे समय में सहायता राशि में कटौती कर रहे हैं जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बावजूद हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए कि महत्वपूर्ण संसाधन सर्वाधिक जरूरतमंदों तक अवश्य ही पहुंचते रहें और यह सहायता लचीली, जवाबदेह एवं देश–संचालित हो। हमें यह अवश्य ही स्मरण रखना चाहिए कि यह निरंतरता, समावेशिता और समृद्धि में एक अच्छा निवेश है।'

यह बात रेखांकित करते हुए कि महामारी और आने वाले वैश्विक आर्थिक

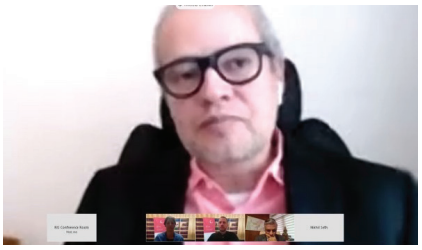

संकट के परिणामस्वरूप विकास सहयोग भारी दबाव में है, श्री मून ने कहा कि एजेंडा 2030 के आह्वान, ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने और वर्तमान महामारी के कहर से निपटने के तरीकों की खोज के तहत

...शेष पृष्ठ 14 पर

विकास वित्त संस्थान

आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री राकेश मोहन ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि प्रस्तावित नए विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) को 'दीर्घकालिक पूंजी' निवेशकों के साथ–साथ इसके बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन में प्रमुख विशेषज्ञों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। श्री मोहन, जो आईएमएफ में एक पूर्व कार्यकारी निदेशक भी थे, ने 19 फरवरी 2021 को आरआईएस और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) द्वारा आयोजित एक वेबिनार के दौरान ये विचार व्यक्त किए।

केंद्रीय बजट 2021–2022 में बुनियादी ढांचागत यानी अवसंरचना क्षेत्र की दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को स्वीकार किए जाने के साथ–साथ 'अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए एक प्रदाता, व्यवस्थापक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने' के लिए एक 'प्रोफेशनल रूप से प्रबंधित' डीएफआई का प्रस्ताव किए जाने के मद्देनजर ही उपर्युक्त विचार व्यक्त किए गए हैं। माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा था कि एक 'डीएफआई' की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने इस संस्थान का पूंजीकरण करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये प्रदान किए थे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा था, 'इस डीएफआई के लिए तीन साल में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षा है।' वित्तीय सेवा विभाग में सचिव श्री देबाशीष पांडा ने कथित तौर पर कहा था कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को नए डीएफआई 'राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक' में सम्मिलित या समाहित किया जा सकता है। प्रस्तावित डीएफआई इसके साथ ही 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिसके तहत लगभग 7,000 परियोजनाओं की पहचान की गई है और जिनमें वर्ष 2020 और वर्ष 2025 के बीच 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश किए जाने का अनुमान है।

श्री राकेश मोहन ने यह भी प्रस्तावित किया कि नए डीएफआई का मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में होना चाहिए और प्रस्तावित डीएफआई का पहला सीईओ या सीएमडी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखे। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री मोहन की राय से सहमति जताते हुए सुश्री श्यामला गोपीनाथ ने यह भी कहा कि सुशासन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अनुबंध पर अमल करने और परियोजना की लाभप्रदता जैसे मुद्दों पर फोकस करने की जरूरत है।

इस अवसर पर आईडीबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ. जी.ए. टाडास ने कहा कि इस संस्थान के पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का बजट प्रस्ताव वर्ष 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली बुनियादी ढांचागत या अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और देश को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो को प्राप्त करने के लिए डीएफआई की आरंभिक पूंजी को बढ़ाकर कम से कम 50,000–60,000 करोड़ रुपये करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है।

प्रोफेसर स्टेफनी ग्रिफिथ–जोन्स, वित्तीय बाजार निदेशक, इनिशिएटिव फॉर पॉलिसी डायलॉग, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने कहा कि डीएफआई का फोकस अब देशों को 'हरित विकास' हासिल करने में मदद करने, नवाचार को बढ़ावा देने, न केवल बुनियादी ढांचागत क्षेत्र को, बल्कि स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अन्य सामाजिक सेक्टरों को भी प्रति–चक्रीय वित्त प्रदान करने पर है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में डीएफआई का कहीं अधिक प्रभाव हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद डीएफआई का पुनरुत्थान देखने को मिल रहा है। ■

'जो बाइडन की सरकार' पर पैनल परिचर्चा

बाइडन द्वारा राष्ट्रपति के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही नए प्रशासन या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 जनवरी 2021 को कार्यभार संभाल लिया। वैश्विक व्यवस्था के विशेष महत्व पर कई अहम टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं। आरआईएस ने 3 फरवरी 2021 को राजदूत मनजीव सिंह पुरी, विशिष्ट फेलो, टेरी एवं पूर्व राजनयिक की अध्यक्षता में वेबिनार का आयोजन किया था जिसमें इसी बात पर फोकस किया गया था कि 'वास्तव में इसके क्या मायने भारत के लिए होंगे'।

इस अवसर पर विशिष्ट पैनलिस्ट ये थेः श्री राजीव खेर, विशिष्ट फेलो, आरआईएस; डॉ. श्रीराम सुंदर चौलिया, प्रोफेसर एवं डीन, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स; डॉ. श्रीकांत कोंडापल्ली, प्रोफेसर, पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; श्री दीपांजन रॉय चौधरी, राजनयिक संपादक, द इकोनॉमिक टाइम्स; और प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, यूरोपीय अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ■

बंगाल की खाड़ी आर्थिक संवाद 2021

आरआईएस स्थित आसियान भारत केंद्र (एआईसी) ने सानेम, बांग्लादेश; भूटानी सोसायटी पर अनुसंधान केंद्र (सीआरबीएस), भूटान; व्यापार, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण पर दक्षिण एशिया निगरानी (सावटी), नेपाल; पाथफाइंडर फाउंडेशन, श्रीलंका; और चुलालॉन्गकॉर्न विश्वविद्यालय, थाईलैंड के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 8–11 फरवरी 2021 को 'बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कोविड–19 के बाद की चुनौतियां' विषय पर बंगाल की खाड़ी आर्थिक संवाद 2021 का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में ये सत्र आयोजित किए गएः डिजिटल कनेक्टिविटी एवं ई–कॉमर्स; व्यापार व क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं; व्यापार, क्षेत्रीय सहयोग, स्वास्थ्य व शिक्षा, रोजगार की चुनौतियों और संबंधित मुद्दों पर शोध–पत्र प्रस्तुति सत्र; बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी; कोविड–19 के बाद बेहतरी के लिए संस्थागत चुनौतियां; बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना; बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कोविड के बाद की चुनौतियों से निपटना; और संबंधित देशों के लोगों के पारस्परिक संपर्कों को मजबूत करना। ■

डिजिटलीकरण और विकासः एशिया से उभरते विचार

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) से 'असाधारण पोर्टेबिलिटी' का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे इसके सभी नागरिकों का देश भर में कहीं भी इलाज किया जा सकेगा और इसके साथ ही उन्हें टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलेगी जिनमें सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के हिस्से के रूप में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्थापित किए जा रहे 150,000 स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों में यह सुविधा मिलना भी शामिल है।

एनडीएचएम के 'स्वास्थ्य डोमेन सिद्धांतों' के अनुसार, 'एनडीएचएम की मौजूदगी पूरे देश में होगी और यह एक हेल्थ आईडी – व्यक्तिगत स्वास्थ्य पहचानकर्ता के माध्यम से पूरे देश में निर्बाध पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सूचना मानकों को अपनाने सहित सहायक ब्लॉक राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।'

आरआईएस द्वारा ओईसीडी और ईआरआईए के सहयोग से 5 मार्च 2021 को "डिजिटलीकरण और विकासः एशिया से उभरते विचार' विषय पर आयोजित वेबिनार में डॉ. कुमार ने कहा, 'नीति आयोग एनडीएचएम की स्थापना पर बारीकी से गौर कर रहा है जिसे डिजी–स्टैक में जोड़ा गया है। भारत में पहले से ही डिजी–लॉकर हैं और ऑनलाइन शिक्षा बड़े पैमाने पर चल रही है। एनजीएचएम से हमारे सभी नागरिकों को असाधारण पोर्टेबिलिटी सुलभ होगी, ताकि उनका देश में कहीं भी इलाज किया जा सके और टेलीमेडिसिन तक उनकी पहुंच हो सके, जिसे अब हम बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा रहे हैं।' वेबिनार का आयोजन आरआईएस द्वारा ओईसीडी विकास केंद्र और ईआरआईए, जकार्ता के सहयोग से किया गया।

डॉ. कुमार ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत स्थापित किए जा रहे 150,000 स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों को टेलीमेडिसिन क्षमताओं से लैस किया जाएगा, ताकि मरीजों को व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा सेवा प्रदाताओं यानी डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत न पड़े।

उन्होंने कहा कि सरकार सुव्यवस्थित कृषि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को इस तरह से प्रोत्साहित कर रही है जिससे कि पानी के संरक्षण में मदद मिले और देश को विकास एवं पर्यावरण के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में मदद मिले, न कि इनमें से एक को पाने के बदले में दूसरे को गंवाना पड़ जाए।

प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा का उल्लेख करते हुए कि अगले 1,000 दिनों में भारत के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, उन्होंने कहा कि 150,000 ग्राम पंचायतों को पहले ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है एवं अगले दो वर्षों में 100,000 और ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, 'फिर हम इसे हर गांव में फैलाना चाहते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी गांवों को पहले ही बिजली प्रदान कर दी है।' उन्होंने यह भी कहा, 'हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल तकनीक सभी के लिए सुलभ हो।'

उन्होंने कहा कि देश भर में खोले गए 350,000 साझा सेवा केंद्र (सीएससी) 50 से भी अधिक केंद्रीय योजनाओं और राज्य सरकारों की 300 से भी अधिक योजनाओं से लोगों को अवगत कराने में मदद कर रहे हैं और इसके साथ ही विभिन्न सेवाओं से संबंधित सेवाओं जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र को ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 400 से भी अधिक सरकारी अनुदान योजनाओं का लाभ हस्तांतरित करने में सक्षम रहे हैं। 200,000 और सीएससी जल्द ही स्थापित किए जाने वाले हैं।' उन्होंने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी की विशिष्ट क्षमता एवं संभावनाओं से काफी हद तक परिचित है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह भारत के लिए न केवल हमारे विकास एजेंडे में छलांग लगाने, बल्कि काफी ऊंची छलांग लगाने का भी मौका है और इस तरह से हमारे यहां विकास के प्रतिमान को हर जगह से बिल्कुल अलग दिखाने का अहम अवसर है।

दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत के लिए ओईसीडी का आर्थिक आउटलुक वेबिनार के दौरान 'दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत के लिए ओईसीडी का आर्थिक आउटलुक 2021: डिजिटलीकरण के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण' का भारत में विमोचन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, 'कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में विकास में आई सुस्ती उभरते एशिया (आसियान–10, चीन और भारत) को काफी हद तक प्रभावित करेगी।' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, 'वर्ष 2021 में ज्यादातर उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक उत्पादन के महामारी पूर्व स्तरों पर लौटने की संभावना नहीं है।'

डॉ. केंसुके तनाका, एशिया डेस्क के प्रमुख, ओईसीडी विकास केंद्र, पेरिस ने कहा कि भारत की आर्थिक चुनौतियों में किसी ठोस युक्ति या उपाय के लिए कम होती मौद्रिक एवं राजकोषीय गुंजाइश, ढांचागत मुद्दों (जैसे कि वित्तीय प्रणाली के कमजोर होने; विनिर्माण संबंधी चुनौतियां; बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी; विशेषकर छोटी

फर्मों के बीच डिजिटलीकरण का स्तर) और बढ़ती असमानताएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ता कर्ज स्तर भारत सहित कई देशों में कर्ज अदायगी क्षमता के कम हो जाने का जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, 'जब तक कोविड–19 के खिलाफ कोई प्रभावकारी या कारगर टीका व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक वायरस का संचरण स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर काफी दबाव डालता रहेगा। इस तरह के हालात में सामाजिक पाबंदियों को समय पर वापस लिया जाना और सामान्य आर्थिक स्थितियों की बहाली भी संभव नहीं हो पाएगी।' रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति निर्माताओं को इस अवधि के दौरान अपनी महामारी प्रबंधन रणनीतियों का निरंतर विस्तार करने और इसके साथ ही टीकों के कुशल भंडारण एवं समान वितरण की गारंटी देने की जरूरत है।

रिपोर्ट के अनुसार, 'डिजिटल स्वास्थ्य उद्योग द्वारा महामारी के दौरान अपनी सेवाओं का विस्तार किए जाने को देखते हुए नीति निर्माताओं को डेटा की सुरक्षा के लिए एक ऐसी स्पष्ट कानूनी रूपरेखा स्थापित करने की आवश्यकता है जो मरीजों से जुड़े डेटा के संग्रह, भंडारण, प्रोसेसिंग और साझाकरण का उचित नियमन करे।' रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को विश्वसनीय, किफायती और उपयोग में अत्यंत आसान उपकरणों तक लोगों की समान पहुंच सुनिश्चित करके डिजिटल स्वास्थ्य लाभों के समान वितरण की गारंटी देनी चाहिए।

श्री शेषाद्री चारी, सदस्य, संचालन परिषद, आरआईएस; डॉ. मारियो पेजिनी, निदेशक, ओईसीडी विकास केंद्र, पेरिस; और डॉ. नागेश कुमार, निदेशक, यूएनएस्कैप, एसएसडब्ल्यूए कार्यालय, भारत ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त, किए। डॉ. प्रियदर्शी दाश, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस ने वेबिनार के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए और धन्यवाद ज्ञापन किया। ■

मुक्त, खुले और समावेशी हिंद–प्रशांत के लिए कनेक्टिविटी सहयोग

आरआईएस और आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने नई दिल्ली स्थित जापान के दूतावास (ईओजे) और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 18 मार्च 2021 को वर्चुअल मोड में 'मुक्त, खुले और समावेशी हिंद–प्रशांत के लिए कनेक्टिविटी सहयोग' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में स्वागत भाषण प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने और उद्घाटन भाषण डॉ. मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस ने दिया। माननीय श्री सतोशी सुजुकी, राजदूत असाधारण और पूर्णाधिकारी, जापान दूतावास, नई दिल्ली ने विशेष भाषण दिया। श्रीमती रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उद्घाटन भाषण दिया। दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। सत्र I: कनेक्टिविटी परियोजनाओं के सर्वोत्तम तरीके, और सत्र II: नियम–आधारित कनेक्टिविटी सहयोग।

सत्र I की अध्यक्षता श्री रजत नाग, विशिष्ट फेलो, एनसीएईआर और पूर्व एमडीजी, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), नई दिल्ली ने की। सत्र I में वक्तागण ये थेः श्री ताकेओ कोनिशी, कंट्री डायरेक्टर, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), नई दिल्ली; श्री जगजीत सिंह, उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), गुरुग्राम; और डॉ. योस रिजल दामुरी, अनुसंधान निदेशक, रणनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (सीएसआईएस), जकार्ता। सत्र II की अध्यक्षता डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आरआईएस, नई दिल्ली ने की। सत्र II में वक्तागण ये थेः प्रो. फुकुनारी किमुरा, कीओ विश्वविद्यालय, टोक्यो, एवं मुख्य अर्थशास्त्री, आसियान व पूर्वी एशिया का आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता; और डॉ. जयंत मेनन, विजिटिंग फेलो, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान (आईएसईएएस), सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूएस) , सिंगापुर।■

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारत–ताइवान सहयोग

...पृष्ठ 9 से आगे

कल्याण राम, सीईओ, इलेक्ट्रोनो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एवं उप निदेशक, स्वचालन उद्योग संघ; और डॉ. दीपनविता चट्टोपाध्याय, चेयरमैन व सीईओ, आईकेपी नॉलेज पार्क। ताइवान की ओर से मुख्य वक्ता ये थेः डॉ. रॉय ली, वरिष्ठ उप निदेशक, ताइवान डब्ल्यूटीओ एवं आरटीए केंद्र, चुंग–हुआ आर्थिक अनुसंधान संस्थान (सीआईईआर); श्री स्टेनली वांग, उप महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, सूचना उद्योग संस्थान; डॉ. याउ–जूनियर लियू, उपाध्यक्ष, ताइपे समुद्री प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय; और सुश्री विवियन हुआंग, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, सूचना उद्योग संस्थान। ■

विकास वित्त संस्थानों का स्वरूप, नए अवसर और नीतिगत विकल्प

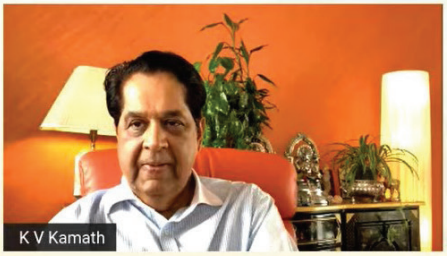

जैसा कि पहले बताया गया था, आरआईएस ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बैंकिंग और वित्त पर वेबिनार की नई श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला के भाग के रूप में पहला वेबिनार 'भारत में घटती बचत दर – नए नीतिगत विकल्प' (20 जनवरी 2021) और दूसरा वेबिनार 19 फरवरी 2021 को विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) पर आयोजित किया गया था। इस श्रृंखला में तीसरा वेबिनार 17 मार्च 2021 को 'विकास वित्त संस्थानों को सही स्वरूप देना: नए अवसर और नीतिगत विकल्प' पर आयोजित किया गया था।

बजट 2021 में विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की स्थापना की घोषणा की गई है। वैसे तो डीएफआई के बारे में विवरण अब भी प्रतीक्षित है, लेकिन यह बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के बारे में दीर्घकालिक विजन विकसित करने और घरेलू संसाधनों को जुटाने के लिए कई तौर–तरीकों का अध्ययन करने का व्यापक अवसर देता है। उभरते परिदृश्य के संदर्भ में इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पैनल परिचर्चा के दौरान इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर फोकस किया गया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। पैनलिस्टों में श्री के.वी. कामथ, पूर्व प्रेसिडेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक; डॉ. विश्वपति त्रिवेदी, पूर्व सचिव, भारत सरकार; डॉ. पार्थ मुखोपाध्याय, सीनियर फेलो, नीतिगत अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली; और श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, सहायक सीनियर फेलो, आरआईएस शामिल थे। ■

संयुक्त राष्ट्र@75 और दक्षिणीय सहयोग: उभरती भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

...पृष्ठ 10 से आगे

वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं मुहैया कराने एवं सर्वसुलभ संसाधनों के संरक्षण के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की भी सख्त आवश्यकता है।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और उभरती ताकतों दोनों से ही वैश्विक व्यवस्था में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'आपके देश हमारे बहुपक्षीय भविष्य का ख्याल रखते हैं। वास्तव में, जब आपने लाखों लोगों को गरीबी से उबारा है, तो आप लाखों और लोगों की मदद अवश्य कर सकते हैं।' श्री मून ने कहा कि जहां एक ओर कोविड–19 महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और सामूहिक प्रयासों की कड़ी परीक्षा ली है, वहीं दूसरी ओर इसने आपसी सहयोग बढ़ाने के अवसर भी पैदा किए हैं, ताकि इस महामारी से जल्द उबरने में मदद मिल सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पीछे न छूटे। इस वेबिनार के दौरान विकासशील देशों (दक्षिणीय सहयोग या एसएससी) के बीच सहयोग से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई, ताकि इन देशों को मौजूदा कोविड–19 संकट से बेहतर तरीके से उबरने में मदद मिल सके। वर्ष 2013 से ही दक्षिणी प्रदाताओं का सम्मेलन (दिल्ली प्रक्रिया) एसएससी से जुड़े मुद्दों और उभरती चुनौतियों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करता रहा है। एसएससी के लिए संयुक्त राष्ट्र का समर्थन इन प्रयासों का एक अभिन्न अंग रहा है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ इस बात पर गौर करने के लिए ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है कि संयुक्त राष्ट्र और 'दक्षिण' यानी इसके अधिकतर सदस्य देशों के बीच संबंध आखिरकार किस तरह से विकसित हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पूर्व विशेष सलाहकार राजदूत विजय नांबियार; डॉ. स्वेन ग्रिम, अंतर– और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रशिक्षण, डीआईई पर अनुसंधान कार्यक्रम के प्रमुख; और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में प्रतिष्ठित पैनलिस्टों के साथ चर्चा भी की गई। विवरण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ■

आपदा जोखिम प्रबंधन पर *'डीसीआर'* के विशेष अंक का विमोचन

आरआईएस 'विकास सहयोग समीक्षा (डीसीआर)' नामक विशिष्ट पत्रिका प्रकाशित करता है जो वैश्विक विकास सहयोग से जुड़ी समग्र गाथा या विवरण को प्रस्तुत करने और दक्षिणी या विकासशील देशों की अगुवाई में विकास सहयोग प्रक्रिया के सिद्धांत, अनुभवजन्य सत्यापन और प्रलेखन या पुष्टिकरण में व्याप्त महत्वपूर्ण ज्ञान अंतर को पाटने की आकांक्षा रखती है। 'आपदा जोखिम प्रबंधन' पर इस पत्रिका के एक विशेष अंक का विमोचन किया गया जिसमें भारतीय संदर्भ के साथ–साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक संदर्भ में भी कोविड–19 और संबंधित आयामों के आधार पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

इस 'विशेष अंक' का वर्चुअल विमोचन 5 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया। इसके बाद एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी,

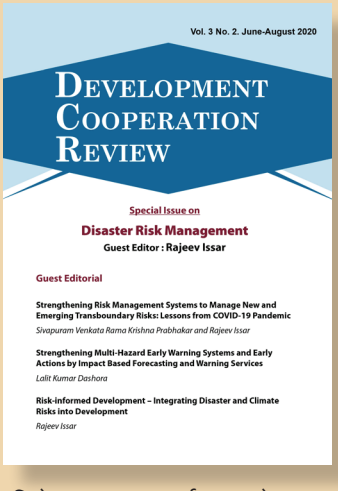

महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण और श्री राजीव इस्सर, यूएनडीपी, क्राइसिस ब्यूरो, ग्लोबल डीआरआर टीम द्वारा इस विशेष अंक के संदर्भ निर्धारण के साथ हुई। 'डीसीआर' के प्रबंध संपादक प्रोफेसर मिलिंदो चक्रबर्ती ने *'डीसीआर'* के बारे में जानकारी दी। श्री कमल किशोर, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। श्री अखिलेश मिश्रा, अपर सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने सत्र की अध्यक्षता की। श्री राजीव इस्सर ने भी पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता की। पैनलिस्ट ये थेः डॉ. एमिली विलकिंसन, विदेश विकास संस्थान (ओडीआई), लंदन; डॉ. ए. सुब्बैया, निदेशक, क्षेत्रीय एकीकृत बहु–जोखिम ईडब्ल्यू सिस्टम (आरआईएमईएस), बैंकॉक; और श्री गतकुओथ काई, डीआरआर के तकनीकी समन्वयक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि विभाग, एयू आयोग। राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। डॉ. मोना छाबड़ा, निदेशक, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) ने समापन भाषण दिया।

विस्तृत विवरण के लिएः http://ris.org.in/journals-n-newsletters/Development-Cooperation-Review ■

शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार के लिए आदर्श माहौल

34वां स्टिप फोरम व्याख्यान 24 मार्च 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मुख्य नवाचार अधिकारी डॉ. अभय जेरे ने दिया। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय 'शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार के लिए आदर्श माहौल बनाना' था। इस कार्यक्रम का संचालन विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉ. नकुल पाराशर ने किया। डॉ. किंकिनी दासगुप्ता मिश्रा, वैज्ञानिक–एफ, विज्ञान प्रसार ने स्वागत भाषण दिया।

डॉ अभय जेरे ने अपने अत्यंत सहज संबोधन में भारत में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में एक जीवंत और आदर्श माहौल बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि शैक्षणिक संस्थानों में एक ऐसे व्यवस्थित माहौल या परिवेश का नितांत अभाव है, जो विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है एवं उन्हें और भी अधिक रचनात्मक होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्होंने लीक से हटकर सोचने और अभिनव आइडिया विकसित करने एवं उसका अधिकार अपने पास रखने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को या तो अपने अभिनव आइडिया को प्रौद्योगिकी में बदलने का प्रयास करना चाहिए या उन्हें अपने बेहतरीन आइडिया के लिए आईपीआर/पेटेंट प्राप्त करना चाहिए। डॉ. जेरे ने एक ऐसा आदर्श माहौल या परिवेश (इकोसिस्टम) बनाने पर जोर दिया जो विद्यार्थियों या शोधकर्ताओं को अपने अभिनव आइडिया और सृजन के लिए पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करे। उन्होंने एक वार्षिक 'स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन' आयोजित करने की अपनी स्वयं की पहल के बारे में विस्तार से बताया, जो अब 'दुनिया के सबसे बड़े हैकाथॉन और सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल' के रूप में विकसित हो गया है। डॉ. जेरे ने भारत में सभी शिक्षण संस्थानों को उनकी नवाचार उपलब्धियों पर उन्हें रैंकिंग देने के लिए अपनी तरह के पहले 'अटल इनोवेशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (एआरआईआईए)' को अमल में लाए जाने के बारे में चर्चा की।

उन्होंने यह भी बताया कि 'संकाय एवं विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्ट–अप नीति 2019', जो उनके द्वारा ही स्टार्ट–अप संस्कृति और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी, उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को किस तरह से अपने–अपने नवाचार, स्टार्ट–अप और उद्यमों पर आगे काम करने में सक्षम बना रही है। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने डॉ. जेरे द्वारा परिकल्पित 'नवाचार और उद्यमिता' में एक अनूठे एमबीए प्रोग्राम की भी घोषणा की है।

अपने भाषण के आखिर में वक्ता जेरे ने भारत में शैक्षणिक संस्थानों में मौजूदा माहौल या परिवेश (इकोसिस्टम) को व्यापक रूप से सुधारने की अनिवार्यता और देश में 'नवाचार–संस्कृति' को बढ़ावा देने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया।■

ब्रिक्स सिविल फोरम 2021: साझेदारों से परामर्श

परामर्श में उपस्थित गणमान्य प्रतिभागी।

अप्रैल 2021 में ब्रिक्स सिविल फोरम पूर्वावलोकन के लिए अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में आरआईएस ने 27 मार्च, 2021 को वर्चुअल प्रारूप में 'साझेदारों के बीच परामर्श' का आयोजन किया। सभी ब्रिक्स देशों के प्रमुख सीएसओ और थिंक–टैंकों के कई शोधकर्ताओं/प्रोफेशनलों ने इस आयोजन में भाग लिया। ब्रिक्स सिविल फोरम की वेबसाइट को इस बैठक में लॉन्च किया गया जो ब्रिक्स सिविल फोरम की समस्त गतिविधियों के लिए सूचना भंडार होगी। इससे पहले आरआईएस ने 21 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में श्री पी. हरीश, भारत के ब्रिक्स सूस शेरपा और भारत के अनेक सीएसओ के प्रतिनिधियों के एक समूह के साथ एक आंतरिक संवाद का आयोजन किया था।

साझेदारों के बीच परामर्श में उद्घाटन सत्र शामिल था जिसके बाद इन चार प्रमुख मुद्दों पर राय एवं सुझाव मांगने के लिए एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गई: विभिन्न थीम का विकल्प; संसाधन व्यक्ति एवं हितधारक; समेकन का प्रारूप; और अपेक्षित परिणाम। इस बैठक का मार्गदर्शन और संचालन आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने किया।

संदर्भ निर्धारण के दौरान प्रोफेसर चतुर्वेदी ने ब्रिक्स सिविल फोरम में उन प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया, जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है जैसे कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2021 की 3सी (निरंतरता, समेकन और आम सहमति) वाली थीम के साथ ब्रिक्स सिविल फोरम के एजेंडे को कैसे समायोजित करें। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि ब्रिक्स सिविल फोरम को आखिरकार कैसे संस्थागत स्वरूप दिया जाए, जैसा कि ब्रिक्स अकादमिक फोरम (ब्रिक्स थिंक–टैंक काउंसिल यानी बीटीटीसी बनाकर) के मामले में किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि ब्रिक्स सिविल के व्यापक प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या होने चाहिए; ब्रिक्स सिविल को कैसे समेकित या एकीकृत किया जाए; सिविल फोरम को एक स्थायी प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जाए; भागीदारी बढ़ाने के लिए पी2पी को कैसे बढ़ाया जाए; और ब्रिक्स सिविल को और भी अधिक जीवंत फोरम कैसे बनाया जाए।

राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समय–समय पर ब्रिक्स के एजेंडे में विभिन्न महत्वपूर्ण थीम और विषयों को शामिल करने का उल्लेख किया। इन विषयों में से एक विषय रूस में वर्ष 2015 में 'ब्रिक्स सिविल फोरम' की स्थापना करना था। ■

भारत के साथ त्रिकोणीय सहयोग में वैश्विक रुझान

...पृष्ठ 7 से आग

संस्थागत स्वरूप देने के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) कार्यक्रम बनाया था। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से भारत ने बहुपक्षीय पहलों में अपनी सहभागिता बढ़ा दी है, ताकि विकासशील देशों के साथ अपने सहयोग को बढ़ाया जा सके। भारत इसके साथ ही जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इत्यादि सहित कई साझेदार देशों के साथ त्रिकोणीय सहयोग में जुटा रहा है।

भारत सरकार दक्षिणीय सहयोग के सिद्धांतों के लिए अब भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में त्रिकोणीय सहयोग के प्रति भारत का नजरिया वर्ष 2014 से और भी अधिक विकसित हुआ है। अब ओईसीडी और डीएसी के सदस्य देशों के साथ अपेक्षाकृत अधिक जुड़ाव है। इस शोध–पत्र (पेपर) में भारतीय त्रिकोणीय सहयोग को बढ़ाने में सिविल सोसायटी की भूमिका का उल्लेख किया गया है और इसके साथ ही यह बताया गया है कि भारत के साथ त्रिकोणीय साझेदारियों के लिए नए अवसर खुल गए हैं। सीएसओ भारत के साथ त्रिकोणीय साझेदारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीएसओ ने कई सामाजिक और आर्थिक नीतिगत क्षेत्रों पर काम किया है। भारतीय सीएसओ ने भारत में लंबे समय से चले आ रहे कई घरेलू मुद्दों को प्राथमिकता दी है और उन पर फोकस किया है। उन्होंने गरीबी, असमानता और लोगों को अलग–थलग रखे जाने के मुद्दों को सुलझा करके भारत में हाशिए पर पड़े विभिन्न समूहों के लाभ के लिए काफी काम किया है। राजस्थान स्थित बेयरफुट कॉलेज एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जहां भारतीय सीएसओ को दक्षिणीय सहयोग से जुड़ने के लिए सरकार से आवश्यक सहयोग प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, 'आधार (बायो–मीट्रिक)' पर आधारित सेवाओं की डिलीवरी जैसे भारत के प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़े अनुभव दरअसल कुछ ऐसी विकासात्मक पहल हैं जिन्हें अन्य विकासशील देशों में भारतीय सीएसओ द्वारा दोहराया जा सकता है। ■

आरआईएस संकाय

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

- 24 मार्च 2021 को देव संस्कृति, इंडिया थिंक काउंसिल और पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित कुंभ सम्मेलन 2021 में सतत विकास लक्ष्यों पर वीडियो संदेश दिया।
- 19 मार्च 2021 को आरबीआई बोर्ड की बैठक में भारत–चीन व्यापार घाटा और व्यापक व्यापार परिदृश्य पर प्रस्तुति दी।
- 17 मार्च 2021 को यूएनओएसएससी द्वारा आयोजित विकास सहयोग के लिए महानिदेशकों पर उच्च स्तरीय फोरम में 'एसएससी और त्रिकोणीय सहयोग के लिए कोविड–19 संकट से उत्पन्न रुझान, अवसर एवं चुनौतियां' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 13 मार्च 2021 को द एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन–2021: मानसिक स्वास्थ्य– 'अवसाद से अच्छी सेहत की ओर' में 'बेहतर मानसिक स्वास्थ्य परिणामों के लिए आर्थिक प्रतिबद्धताएं और मानसिक विकारों की बीमा कवरेज: विमुखता के कारण और समाधान' पर प्रस्तुति दी।
- 9 मार्च 2021 को हैन्स सीडेल फाउंडेशन (एचएसएफ) द्वारा 'विश्व मामलों के फोकस में चीन और भारत' पर आयोजित नई ऑनलाइन श्रृंखला में 'आरसीईपी और एशिया एवं यूरोप के लिए परिणाम' पर प्रस्तुति दी।
- 26 फरवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम ब्रिक्स और सूस शेरपा बैठक में 'ब्रिक्स सिविल फोरम 2021' पर प्रस्तुति दी।
- 17 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 2020 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं की संगोष्ठी में 'दक्षिणीय सहयोग'' पर प्रस्तुति दी।
- 9 फरवरी 2021 को ओईसीडी द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भविष्य' विषय पर आयोजित विशेषज्ञों के कार्यदल के तीसरे विचार–मंथन सत्र में भाग लिया।
- 2 फरवरी 2021 को दूरदर्शन द्वारा भारत–बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की शुरुआत की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित पैनल परिचर्चा में 'भारत–बांग्लादेश' पर प्रस्तुति दी।
- 28 जनवरी 2021 को हैन्स सीडेल फाउंडेशन (एचएसएफ) द्वारा 'विश्व मामलों के फोकस में चीन और भारत' पर आयोजित ऑनलाइन श्रृंखला में 'आरसीईपी पर फोकस के साथ भारत एवं चीन के आर्थिक संबंध और भारत के लिए इसके भू–आर्थिक निहितार्थ' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 21 जनवरी 2021 को जर्मन अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र (डीडब्ल्यूआईएच) और जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डीएएडी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'भारत–जर्मन संवाद: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विज्ञान कूटनीति' में पैनलिस्ट थे।
- 20 जनवरी 2021 को नीतिगत संवाद केंद्र (सीपीडी), ढाका द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया में विदेशी उच्च शिक्षा के लिए रिटर्न पर प्रस्तावित सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना की 'आरंभिक बैठक' में भाग लिया।
- 12 जनवरी 2021 को विकास अध्ययन केंद्र (सीडीएस) द्वारा 'भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व संबंधी दिशा–निर्देश और कॉरपोरेट संरचना' पर आयोजित वर्चुअल पैनल परिचर्चा के दौरान 'भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व संबंधी दिशा–निर्देश और कॉरपोरेट संरचना' पर प्रस्तुति दी।

प्रोफेसर एस.के. मोहंती

- 22 फरवरी 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 'भारत दक्षिण एशिया अध्ययन: ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंध' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 11 फरवरी 2021 को इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा आयोजित इंडिया एक्जिम बैंक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान वार्षिक (आईईआरए) पुरस्कार 2020 के एक ज्यूरी सदस्य के रूप में पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ सार के चयन के लिए आईईआरए पुरस्कार समिति 2020 की पहली वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
- 9 फरवरी 2021 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सहयोगात्मक पाठ्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय सुव्यवस्थित अध्ययन – सत्र 1ए एवं 1बी में भाग लिया और 'आईओआर में भारत के बढ़ते आर्थिक हित' पर प्रस्तुति दी।
- 9 फरवरी 2021 को सानेम, एआईसी, सावटी, पाथफाइंडर और चुला चुलालॉन्गकॉर्न विश्वविद्यालय, थाईलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'बंगाल की खाड़ी आर्थिक संवाद 2021: बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कोविड–19 के बाद की चुनौतियां (बीओबीईडी 2021)' में भाग लिया और 'शोध पत्र प्रस्तुति सत्र: व्यापार' की अध्यक्षता की।

डॉ. प्रियदर्शी दाश
एसोसिएट प्रोफेसर

- 24 मार्च 2021 को यूएनएस्कैप के नई दिल्ली कार्यालय और बिरूनी संस्थान, अफगानिस्तान द्वारा 'अफगानिस्तान और भूटान में शोधकर्ताओं के लिए विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण में थिंक–टैंकों की भूमिका' पर प्रस्तुति दी।

फेलो/शोधकर्ता

श्री राजीव खेर

विशिष्ट फेलो

- 24 मार्च 2021 को अनंत एस्पेन सेंटर द्वारा 'आरसीईपी–ईयू–चीन–भारत' पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
- 24 मार्च 2021 को आईसीआरआईईआर द्वारा 'व्यापार नीति और व्यापार में सुविधा के लिए सुधारः एक अधूरा एजेंडा' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 17 मार्च 2021 को ट्रू नॉर्थ जर्नीज 2021 में भाग लिया।
- 16 मार्च 2021 को नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित आईपीआरएस 2.0 के लिए गठित संचालन समिति की चौथी बैठक में भाग लिया।
- 12 मार्च 2021 को कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'डेटा गवर्नेंस का भविष्य– विशेषज्ञों की राय सुनें' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 9 मार्च 2021 को कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'समावेशी आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 6 मार्च 2021 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 'डिजिटल युग में रणनीतिक विनिर्माण' पर आयोजित सीआईआई–एसआर की वार्षिक क्षेत्रीय बैठक 2020–21 और उद्योग पुनर्गठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- 22 और 27 जनवरी – 1 फरवरी एवं 6 मार्च 2021 को भारतीय लेखाकार संस्थान द्वारा आयोजित अनुशासनात्मक समिति – पीठ– II की बैठक में भाग लिया।
- 5 मार्च 2021 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 'तीन कृषि कानून और जमीनी हकीकत – भूमि से बाजार तक' पर आयोजित चर्चा में भाग लिया।
- 3 मार्च 2021 को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित हिंद–प्रशांत विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।
- 3 मार्च 2021 को पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द्वारा 'सेवाओं के व्यापार में अधिक खुलापन किस तरह से मजबूत आर्थिक बेहतरी में व्यापक सहयोग दे सकता है?' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 26 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा "पड़ोसी पहलेः म्यांमार में तख्तापलटः भारत के लिए निहितार्थ" विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 25 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में आईसीआरआईईआर द्वारा 'भारत की एक्ट ईस्ट नीति को सुगम बनानाः भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एलसीएस में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में कमी का आकलन करना' विषय पर आयोजित कार्यशाला में विशेष भाषण दिया।
- 23 फरवरी 2021 को पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल द्वारा 'आगामी नई विदेश व्यापार नीति 2021–26 से उद्योग की उम्मीदें' विषय पर आयोजित वेबिनार में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया।
- 18 फरवरी 2021 को वाशिंगटन डीसी में इंडो अमेरिकन इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएआईसीसी) के सहयोग से फिक्की द्वारा 'भारत–अमेरिका संबंधों की पुनर्कल्पनाः मोदी–बाइडन–हैरिस युग' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 17 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'समावेशी आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 9 फरवरी 2021 को सीआईआई द्वारा 'भारत–चीन आर्थिक संबंधः भविष्य के रुझान' विषय पर आयोजित सत्र में भाग लिया।
- 4 फरवरी 2021 को आईसीएआई द्वारा पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आईसीएआई आरवीओ) की संचालन परिषद में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 29 जनवरी 2021 को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'हिंद–प्रशांत विशेषज्ञ समूह' की बैठक में भाग लिया।
- 29 जनवरी 2021 को 'सीआईआई की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति परिषद' की बैठक में भाग लिया।
- 28 जनवरी 2021 को फिक्की द्वारा कोनराड एडेनॉयर स्टिफ्टुंग (केएएस), ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) एवं राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एनएमएफ) के सहयोग से 'नीली अर्थव्यवस्थाः उभरते क्षेत्र और नई प्रौद्योगिकियां' विषय पर आयोजित परिचर्चा में भाग लिया।
- 27 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'समावेशी आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 22 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 'चीन पर सीआईआई के कोर ग्रुप' के एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में एयरटेल बैंक द्वारा 'बैंक की प्रगतिशील रणनीति और वित्तीय स्थिति' विषय पर आयोजित परिचर्चा में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।

डॉ. बी. बालाकृष्णन

विज्ञान कूटनीति फेलो

- 22 मार्च 2021 को नीतिगत अनुसंधान के लिए डीएसटी केंद्रों के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित डीएसटी विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया।
- 10 फरवरी 2021 को एवरिस्टर, पेरिस, फ्रांस द्वारा 'भारत की विज्ञान कूटनीति की महत्वाकांक्षाएं और उपलब्धियां' विषय पर आयोजित वेबिनार में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 24 जनवरी 2021 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 'स्टिप' पर आयोजित विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया।

डॉ. पी.के. आनंद

विजिटिंग फेलो

- 22 मार्च 2021 को आयोजित सह–लेखकों की टी20 टास्क फोर्स 6 की बैठक में भाग लिया, ताकि इस पर नीतिगत सार प्रस्तुत किया जा सके कि 'हम कैसे जानते हैं कि बचपन की नीतियों और प्रथाओं की निगरानी, आकलन एवं योजना बनाना प्रभावकारी एवं सुदृढ़ सामाजिक कल्याण प्रणालियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है' जिसमें 'प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा' शामिल है।
- 2 मार्च 2021 को एसडीजी 12, जो सतत उपभोग और उत्पादन के महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करता है, पर टेरी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सलाहकार गोलमेज संवाद में नीति और आकलन के मुद्दों पर एक चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

- 25 फरवरी 2021 को एसडीजी के लिए एसटीआई पर कामकाज को आगे बढ़ाने हेतु विचार–विमर्श के लिए भारत सरकार के डीएसटी में वैज्ञानिक सचिव के साथ बैठक में भाग लिया। परियोजना के तहत आरआईएस प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय का ज्ञान साझेदार है, क्योंकि भारत भी प्रौद्योगिकी सुविधा व्यवस्था पर पायलट कार्यक्रम में अनेक साझेदार देशों में से एक है।
- 10 फरवरी 2021 को आसियान में भारतीय राजदूत के साथ बैठक में भाग लिया, जिसमें आरआईएस टीम के एक सदस्य के रूप में आसियान–भारत सहयोग एवं इसके व्यापक संदर्भ से अवगत कराया और विचार–विमर्श किया।

श्री कृष्ण कुमार

विजिटिंग फेलो

- 10 फरवरी 2021 को आसियान में भारतीय राजदूत के साथ बैठक में भाग लिया, जिसमें आरआईएस टीम के एक सदस्य के रूप में आसियान–भारत सहयोग एवं इसके व्यापक संदर्भ से अवगत कराया और विचार–विमर्श किया।

नवीनतम प्रकाशन

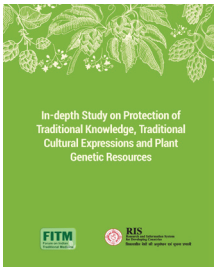

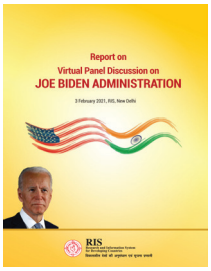

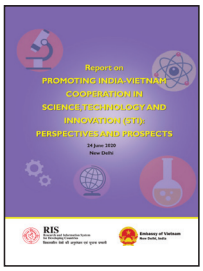

रिपोर्ट

पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण पर गहन अध्ययन, *आरआईएस, एफआईटीएम, नई दिल्ली, 2021*

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) में भारत–वियतनाम सहयोग को बढ़ावा देने पर रिपोर्टः परिप्रेक्ष्य और संभावनाएं, *आरआईएस, वियतनाम दूतावास, नई दिल्ली, 2021*

जो बाइडन की सरकार पर वर्चुअल पैनल चर्चा पर रिपोर्ट, *आरआईएस, नई दिल्ली, 2021*

टीसीएम के राष्ट्रीय और वैश्विक संवर्धन के लिए चीन की नीतिगत पहल *आरआईएस, एफआईटीएम, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली, 2021*

आरआईएस के परिचर्चा पत्र

#263: महामारी के बाद सामाजिक सुरक्षा एजेंडाः सार्वभौमिक बुनियादी आय पर विकासात्मक कदमों को सार्वभौमिक बनाना द्वारा प्रमोद कुमार आनंद और कृष्ण कुमार

#262: कोविड के बाद की चुनौतियांः संयुक्त राष्ट्र को कायापलट की आवश्यकता – इसकी प्राथमिकता और उपयोगिता को फिर से तलाशना *द्वारा अरुणा शर्मा*

#261: दवाओं का व्यापारः भारत का विकास पथ *द्वारा दिनेश कुमार और टी. सी. जेम्स*

#260: महंगाई लक्ष्यीकरणः मौद्रिक नीति, विकास और महंगाई *द्वारा मनमोहन अग्रवाल और अम्मू लावण्या*

आरआईएस का नीतिगत सार

#102 प्रौद्योगिकियों के जरिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में तेजी लाना द्वारा टी. सी. जेम्स

जी20 डाइजेस्ट

- खंडः 2 संख्या : 2, जनवरी, 2021

'एशियाई आर्थिक एकीकरण' पत्रिका

- खंड 3, संख्या 1, अप्रैल 2021

आरआईएस संकाय द्वारा बाह्य प्रकाशनों में योगदान

चतुर्वेदी, सचिन। 2021. समावेशी विकास – सामाजिक क्षेत्र को सक्षम करना, '*योजना*' का विशेष अंक – एक विकास मासिक पत्रिका, मार्च 2021।

चतुर्वेदी, सचिन और अन्य। 2021. भारत के साथ त्रिकोणीय सहयोग में वैश्विक रुझान – सिविल सोसायटी संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए उभरते नीतिगत विकल्प, ओईसीडी का वर्किंग पेपर संख्या 89. जनवरी।

चतुर्वेदी, सचिन। 2021. भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक नए परिदृश्य की आवश्यकता है, मनीकंट्रोल, 7 जनवरी 2021।

चतुर्वेदी, सचिन और अन्य। 2021. विवादित वैश्विक गवर्नेंस के संदर्भ में विकास सहयोग। सचिन चतुर्वेदी, हाइनर जानूस, स्टीफन क्लिंगबील, ली शियाओयुन, आंद्रे डी मेलो ई सूजा, एलिजाबेथ सिदिरोपोलोस और डोरोथिया वेहरमैन (संपादक) में। 2030 एजेंडे को प्राप्त करने के लिए विकास सहयोग की पालग्रेव पुस्तिका। पालग्रेव मैकमिलनः स्विट्जरलैंड।

चतुर्वेदी, सचिन और अन्य। 2021. विकास सहयोग की एक उभरती साझा अवधारणाः 2030 के एजेंडे पर नजरिया। सचिन चतुर्वेदी, हाइनर जानूस, स्टीफन क्लिंगबील, ली शियाओयुन, आंद्रे डी मेलो ई सूजा, एलिजाबेथ सिदिरोपोलोस और डोरोथिया वेहरमैन (संपादक) में। 2030 एजेंडे को प्राप्त करने के लिए विकास सहयोग की पालग्रेव पुस्तिका। पालग्रेव मैकमिलनः स्विट्जरलैंड।

चतुर्वेदी, सचिन और अन्य। 2021. निष्कर्षः 2030 एजेंडे के लिए विकास सहयोग संबंधी अनुभवों का लाभ उठाना – मुख्य संदेश और आगे की राह। सचिन चतुर्वेदी, हाइनर जानूस, स्टीफन क्लिंगबील, ली शियाओयुन, आंद्रे डी मेलो ई सूजा, एलिजाबेथ सिदिरोपोलोस और डोरोथिया वेहरमैन (संपादक) में। 2030 एजेंडे को प्राप्त करने के लिए विकास सहयोग की पालग्रेव पुस्तिका। पालग्रेव मैकमिलनः स्विट्जरलैंड।

चतुर्वेदी, सचिन। 2021. 'आर्थिक सर्वेक्षण ने स्थानीय स्तर पर उत्पादन एवं खपत को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर दिया है', *इंडियन एक्सप्रेस*, 30 जनवरी।

चतुर्वेदी, सचिन और अन्य। 2020. एसडीजी रोडमैप के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पर जी20 का नेतृत्व और वैश्विक पायलट कार्यक्रम की प्रासंगिकता। एसडीजी और विकास सहयोग के लिए जी20 से सहयोग पर टास्क फोर्स 7 – नीतिगत सार, टी20, सऊदी अरब।

डे, प्रबीर। 2021. ओआरएफ में 'बिम्सटेक पल' (2021) 2021 में बिम्सटेक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), कोलकाता।

डे, प्रबीर। 2021. 'कोविड–19 के बाद की अवधि में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण', *आर्टनेट का वर्किंग पेपर* रु 204, यूएनएस्कैप, बैंकाक।

डे, प्रबीर। 2021. 'कृपया धैर्य रखें: भारत की आसियान यात्रा को अभी बहुत आगे जाना है', *द मिंट*, 25 फरवरी 2021, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर। 2021. 'आसियान के साथ साझेदारी करना और कोरिया की नई दक्षिणी नीतिः भारत से उभरते विचार, विश्व अर्थव्यवस्था का सार, खंड 11, संख्या 13, *कीप*, सियोल, 19 मार्च, 2021।

मोहंती, एस.के.। 2021. एशिया–अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोरः हिंद–प्रशांत क्षेत्र में विकास और सहयोग' में 'अफ्रीका में व्यापार सुविधा में भारत–जापान सहयोग के लिए संभावनाएं' और 'अफ्रीका में नीली अर्थव्यवस्था में आर्थिक अवसर' पर अध्याय। स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, जनवरी।

मोहंती, एस.के.। 2021. 'भारत–अमेरिका व्यापार वार्ताः व्यापार सौदे के मुद्दे'। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

पीटर, ऑगस्टीन। 2021. 'डब्ल्यूटीओ के नए महानिदेशक की प्राथमिकताएं अवश्य होनी चाहिए'। *फाइनेंशियल एक्सप्रेस*, 24 फरवरी।

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर IV-B, चौथी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत। दूरभाष 91–11–24682177–80
फैक्सः 91–11–24682173–74, ईमेलः dgoffice@ris.org.in
वेबसाइटः www.ris.org.in

हमें यहां फॉलो करें:

www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi